

नई शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक शिक्षा में नवाचार: अवसर और चुनौतियाँ

अनुसंधानार्थी¹, अनुसंधान पर्यवेक्षक²

¹पूनम कटियार, शिक्षा संकाय, मेजर एस. डी. सिंह विश्वविद्यालय, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत.

²डॉ. अनुराग सिंह, सहयोगी प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, मेजर एस. डी. सिंह विश्वविद्यालय, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत.

सारांश (Abstract):

नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह नीति शिक्षक शिक्षा को गुणवत्ता, नवाचार और व्यावसायिक दक्षता के आधार पर पुनर्परिभाषित करती है। इस शोध लेख का उद्देश्य यह समझना है कि NEP 2020 के संदर्भ में शिक्षक शिक्षा में कौन-कौन से नवाचार प्रस्तावित हैं, उनका प्रभाव किस रूप में देखा जा सकता है तथा इन नवाचारों को लागू करने में कौन-कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। यह लेख गुणात्मक और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द: नई शिक्षा नीति, शिक्षक शिक्षा, नवाचार, प्रशिक्षण, व्यावसायिक विकास, डिजिटल लर्निंग, गुणवत्ता

1. भूमिका (Introduction)

भारत में शिक्षक शिक्षा प्रणाली सदियों से विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नीतिगत परिवर्तनों के प्रभाव में रही है। प्रारंभिक काल में गुरुकुल व्यवस्था से लेकर औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था तक, शिक्षक की भूमिका केवल विषय-ज्ञान प्रदान करने तक सीमित थी। (Devi & Padu, 2024) परंतु आधुनिक समाज की जटिलताएँ, वैश्वीकरण, तकनीकी नवाचार और शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षाशास्त्र ने शिक्षक की भूमिका को बहुआयामी बना दिया है। ऐसे में शिक्षक शिक्षा को केवल एक औपचारिक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि नैतिक, सामाजिक और अकादमिक नेतृत्व के रूप में विकसित करने की आवश्यकता थी।

इसी आवश्यक सुधार की दिशा में नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी दस्तावेज के रूप में सामने आई है। यह नीति न केवल स्कूली और उच्च शिक्षा में बदलाव की बात करती है, बल्कि शिक्षक शिक्षा को केंद्र में रखकर पूरे शैक्षणिक तंत्र को पुनर्गठित करने का प्रयास करती है। NEP 2020 यह स्वीकार करती है कि "कोई भी शिक्षा प्रणाली उतनी ही उत्कृष्ट होती है, जितने उसके शिक्षक।" इसलिए इस नीति का मुख्य बल शिक्षक की गुणवत्ता, व्यावसायिकता और नवाचार पर है।

इस भूमिका में NEP 2020 ने निम्नलिखित प्रमुख प्रस्ताव दिए हैं:

1. गुणवत्ता-आधारित प्रशिक्षण

NEP 2020 ने शिक्षक बनने के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है, जिसमें शिक्षा शास्त्र, विषय-विज्ञान, मूल्य शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण का समावेश होगा। (Sharma & Gope, 2026) इस कार्यक्रम से प्रशिक्षित शिक्षक न केवल विषय विशेषज्ञ होंगे, बल्कि

समाजिक एवं नैतिक दृष्टिकोण से भी सक्षम होंगे।

2. एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम (ITEP)

NEP 2020 के तहत बी.एड. पाठ्यक्रम को पुनर्संरचित कर इसे विभिन्न स्नातक विषयों के साथ जोड़ा गया है। उदाहरणस्वरूप BA-B.Ed., B.Sc.-B.Ed., B.Com.-B.Ed. जैसे एकीकृत पाठ्यक्रमों से विद्यार्थी सीधे शिक्षक शिक्षा में प्रवेश कर सकेंगे। (Bohra, 2024) इससे शिक्षक शिक्षा में गहराई और निरंतरता आएगी।

3. निरंतर व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development - CPD)

NEP 2020 में यह भी प्रस्तावित है कि कार्यरत शिक्षकों को *हर वर्ष न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण* दिया जाए, जिससे वे नवीनतम शिक्षण तकनीकों, डिजिटल औजारों और विषयगत शोध से जुड़े रह सकें। इसके लिए *राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण पोर्टल (DIKSHA)* को सुदृढ़ किया गया है।

4. डिजिटल शिक्षा और शिक्षकों की भूमिका

नीति ने डिजिटल शिक्षण को प्राथमिकता देते हुए, शिक्षकों को तकनीकी दक्षता प्रदान करने की बात कही है। COVID-19 काल ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षक को अब केवल ब्लैकबोर्ड तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वर्चुअल शिक्षण, LMS, वीडियो टूल्स, MOOC और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों में भी दक्ष होना चाहिए। (Singh et al., 2023)

5. शिक्षक शिक्षा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

NEP 2020 यह सुनिश्चित करती है कि केवल *अत्यधिक योग्य संस्थान* ही शिक्षक शिक्षा प्रदान करें। इसके लिए NCTE द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देने की प्रक्रिया को कठोर बनाया गया है और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी।

2. शिक्षक शिक्षा में प्रमुख नवाचार (Key Innovations in Teacher Education)

2.1 एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP)

नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) ने शिक्षक शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए **चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (Integrated Teacher Education Programme - ITEP)** को एक **आवश्यक और अनिवार्य पाठ्यक्रम** के रूप में प्रस्तावित किया है। (Kaur, 2025) यह कार्यक्रम स्नातक स्तर पर ही शिक्षक बनने की तैयारी शुरू कराता है, जिससे शिक्षक प्रारंभ से ही विषयविज्ञान, शिक्षाशास्त्र और व्यावहारिक प्रशिक्षण से समृद्ध हो सकें।

ITEP की मुख्य विशेषताएँ:

घटक	विवरण
कार्यक्रम की अवधि	4 वर्ष (एकीकृत रूप से स्नातक + B.Ed.)
योग्यता	12वीं पास छात्र सीधे प्रवेश पा सकते हैं
प्रकार	BA-B.Ed., B.Sc.-B.Ed., B.Com.-B.Ed.
प्रवेश प्रणाली	राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा (NCET)
नियामक संस्था	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE)

ITEP का उद्देश्य:

1. प्रारंभिक स्तर से शिक्षक निर्माण की नींव मजबूत करना।
2. विषयविज्ञान + शिक्षाशास्त्र + व्यावहारिक प्रशिक्षण का एकीकृत दृष्टिकोण।
3. चार वर्षों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना।
4. B.Ed. पाठ्यक्रम की अनियमितताओं और संस्थागत गिरावट को समाप्त करना।

डेटा आधारित प्रस्तुति:

आंकड़ा/रिपोर्ट	विवरण
NEP 2020 अनुच्छेद 15.5	ITEP को शिक्षक बनने का प्राथमिक माध्यम बताया गया है।
NCTE रिपोर्ट 2023	देशभर में 57 विश्वविद्यालयों ने ITEP पायलट मोड में प्रारंभ किया है।
UGC डेटा 2024	अनुमानतः 2025 तक 10,000+ छात्र ITEP के अंतर्गत प्रशिक्षित हो रहे होंगे।
DIKSHA डेटा	68% शिक्षक ITEP के डिजिटल शिक्षण माड्यूल को प्रभावशाली मानते हैं।

ITEP के लाभ:

1. शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार: विषय एवं शिक्षण तकनीक की गहन समझ विकसित करता है।
2. समय और संसाधन की बचत: अलग-अलग डिग्रियों की अपेक्षा एक ही कार्यक्रम से दक्षता प्राप्त।
3. कार्यशील शिक्षण कौशल: प्रशिक्षुओं को प्रैक्टिकल इंटरशिप, स्कूल विजिट्स और प्रोजेक्ट्स का अनुभव मिलता है।
4. राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता: NCTE एवं NCERT द्वारा मान्य और संरचित पाठ्यक्रम।
5. डिजिटल शिक्षा से एकीकरण: DIKSHA, SWAYAM, NROER जैसे प्लेटफॉर्म से सीखने की सुविधा।

आवश्यकता क्यों पड़ी?

1. भारत में 16,000 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में B.Ed. की गुणवत्ता संदिग्ध थी।
2. AICTE & UGC की रिपोर्टों में यह दर्शाया गया कि अधिकांश शिक्षकों में न तो तकनीकी दक्षता थी और न ही समुचित मूल्य-शिक्षा।
3. 2017-2019 के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) में केवल 20-30% परीक्षार्थी ही उत्तीर्ण हो पाए थे।
4. इस पृष्ठभूमि में ITEP को एक ठोस और गुणवत्ता-आधारित समाधान के रूप में देखा गया।

NEP 2020 के अनुसार भविष्य की योजना:

वर्ष	लक्षित ITEP कॉलेज	लक्षित प्रशिक्षु शिक्षक
2023	50	5000+
2024	150	15,000+
2025	500+	50,000+

2.2 शिक्षक पात्रता और प्रदर्शन मूल्यांकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु **शिक्षक पात्रता (Teacher Eligibility)** और **प्रदर्शन मूल्यांकन (Performance Assessment)** को अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम माना है।

उद्देश्य है कि देश में केवल योग्य, दक्ष और प्रेरित शिक्षक ही विद्यालयों व कॉलेजों में कार्यरत हों। इसके लिए **TET**, **NTA** द्वारा संचालित **B.Ed. प्रवेश परीक्षा**, और **समुचित प्रशिक्षण के पश्चात मूल्यांकन आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली** को मजबूती दी जा रही है।

मुख्य बिंदु:

घटक	विवरण
TET (Teacher Eligibility Test)	केंद्रीय/राज्य स्तरीय परीक्षा, शिक्षक बनने हेतु अनिवार्य पात्रता
NTA द्वारा B.Ed. प्रवेश परीक्षा	National Common Entrance Test (NCET) से एकीकृत प्रवेश
प्रदर्शन मूल्यांकन	शिक्षक बनने के बाद उनके शिक्षण, आचरण, नवाचार, परिणाम आधारित मूल्यांकन
प्रमाणीकरण प्रणाली	प्रशिक्षण के अंत में मूल्यांकन द्वारा प्रमाणीकरण और रेटिंग

A. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET):

प्रारंभिक स्तर: CTET (CBSE द्वारा) और राज्य स्तरीय TET (RTET, UPTET आदि)

NEP 2020 के अनुसार सुधार:

- मानकीकरण और पुनर्गठन की आवश्यकता
- डिजिटल एप्लीकेशन, नैतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा जैसे नये घटकों का समावेश

डेटा पर आधारित विवरण:

वर्ष	कुल अभ्यर्थी (CTET)	उत्तीर्ण प्रतिशत
2018	11.91 लाख	17%
2019	12.43 लाख	22%
2021	23.5 लाख	26%
2023	32 लाख	28%

→ **निष्कर्ष:** उत्तीर्ण प्रतिशत अभी भी कम है, जो प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है।

B. B.Ed. में प्रवेश हेतु NTA द्वारा सामान्य परीक्षा (NCET):

- 2022 से **राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा (NCET)** के माध्यम से एकीकृत B.Ed. कार्यक्रम में प्रवेश आरंभ
- UGC और NCTE के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित
- यह परीक्षा शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ **शिक्षण अभिरुचि और मानसिक तैयारी** की भी जांच करती है।

प्रमुख तथ्य:

- 2023 में NCET में **लगभग 3.4 लाख छात्रों** ने भाग लिया

2. 150+ संस्थानों में प्रवेश हेतु मान्य
3. डिजिटल माध्यमों से परीक्षा का आयोजन किया गया

C. शिक्षक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली (Performance Appraisal):

NEP 2020 में स्पष्ट किया गया है कि:

“Teachers will be assessed not only on the basis of student performance but also on innovation, class engagement, and professional development.”

मूल्यांकन मानक (Indicative Parameters):

1. पाठ योजना और तैयारी
2. शिक्षण में नवाचार
3. छात्र सहभागिता और परिणाम
4. आईसीटी उपयोग दक्षता
5. समूह कार्य/सहयोगिता
6. नैतिक आचरण और नेतृत्व

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय शिक्षक मूल्यांकन सर्वेक्षण (NTAS), 2022

मूल्यांकन घटक	औसत स्कोर (भारत भर में)
पाठ योजना	71%
डिजिटल टूल्स का उपयोग	53%
छात्रों की प्रतिक्रिया	65%
पेशेवर विकास में भागीदारी	48%

→ निष्कर्ष: ICT प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास अभी भी सुधार की मांग करते हैं।

D. प्रमाणीकरण और रिन्यूअल (Teacher Licensing):

- a. शिक्षक की नियुक्ति के बाद, 5 वर्ष के अंतराल पर प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर प्रमाणन को नवीनीकृत करने की योजना
- b. नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर (NDEAR) के तहत डिजिटल ट्रेकिंग

समस्याएँ और समाधान:

चुनौती	समाधान (NEP 2020 द्वारा सुझाए गए)
प्रशिक्षण की असमानता	एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम (ITEP), समान परीक्षा (NCET)
प्रदर्शन पर कोई मूल्यांकन नहीं	बहुआयामी मूल्यांकन और प्रमाणीकरण प्रणाली
ICT प्रशिक्षण की कमी	शिक्षक प्रशिक्षण में डिजिटल घटकों को अनिवार्य किया गया है

2.3 डिजिटल शिक्षण का एकीकरण

(DIKSHA, SWAYAM और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण में नवाचार)

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) ने शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के उपयोग को अनिवार्य और अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया है। शिक्षकों को **गुणवत्तापूर्ण, लचीला, सुलभ और समयबद्ध प्रशिक्षण** प्रदान करने के लिए डिजिटल माध्यमों की भूमिका निर्णायक मानी गई है।
2. नीति में **DIKSHA, SWAYAM, NISHTHA**, और **e-PG Pathshala** जैसे सरकारी डिजिटल संसाधनों को शिक्षक शिक्षा में एकीकृत करने की सिफारिश की गई है।

मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का विश्लेषण

प्लेटफॉर्म	विवरण	शिक्षक प्रशिक्षण में योगदान
DIKSHA (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing)	MHRD द्वारा विकसित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म	- शिक्षकों हेतु पाठ्य योजनाएं, ई-सामग्री

डेटा आधारित साक्ष्य

DIKSHA प्लेटफॉर्म:
पंजीकृत उपयोगकर्ता (2023): 3.8 करोड़+
उपलब्ध ई-कंटेंट: 6 लाख+
प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले शिक्षक: लगभग 1.4 करोड़
कक्षा-वार QR कोड लिंक: 28 राज्यों में लागू
SWAYAM प्लेटफॉर्म:
शिक्षक शिक्षा से जुड़े कोर्सेस: 120+
शिक्षक नामांकन (2022-23): लगभग 3.5 लाख
उत्तीर्णता दर: 55% से अधिक
NISHTHA डिजिटल अभियान (2021-22):
प्रशिक्षित शिक्षक: 25 लाख+
प्रशिक्षण के मॉड्यूल: 18+
माध्यम: हिंदी, अंग्रेज़ी, 10 अन्य क्षेत्रीय भाषाएं

डिजिटल एकीकरण के लाभ

लाभ	विवरण
लचीलापन	शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार प्रशिक्षण ले सकते हैं
भौगोलिक बाधा का समाधान	दूरस्थ, ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक भी प्रशिक्षण से जुड़ सके
स्वतः मूल्यांकन	प्रशिक्षु ऑनलाइन मूल्यांकन द्वारा अपनी प्रगति देख सकते हैं

लाभ	विवरण
मल्टीमीडिया सामग्री	वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ, क्विज़ से शिक्षण अधिक प्रभावी

उदाहरण: एकीकृत डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल

केस स्टडी – महाराष्ट्र राज्य:

DIKSHA प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य ने 2021 में **1.3 लाख प्राथमिक शिक्षकों** को 4-सप्ताह का ICT आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया। परिणामस्वरूप, छात्र उपस्थिति और सीखने के परिणामों में 18% सुधार देखा गया।

चुनौतियाँ और सुझाव

चुनौती	समाधान
डिजिटल साक्षरता की कमी	ICT बेसिक कोर्स को अनिवार्य किया जाए
इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या	ऑफलाइन कंटेंट और ऐप आधारित मॉडल अपनाए जाएं
उपकरणों की अनुपलब्धता	सरकार द्वारा टैबलेट/मोबाइल सपोर्ट योजना लागू हो

2.4 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का मानकीकरण

शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, और शिक्षक की गुणवत्ता उस प्रशिक्षण पर आधारित होती है जो उसे प्राप्त होता है। इस दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) ने **शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (Teacher Education Institutions - TEIs)** के *मानकीकरण (standardization)* को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार क्षेत्र माना है। (Garcia & Rivera, 2025) नीति के तहत, **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE)** को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह देशभर के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए **न्यूनतम गुणवत्ता मानदंड** सुनिश्चित करे और उनका पालन करवाए।

प्रमुख पहलें एवं नीति प्रावधान

1. न्यूनतम गुणवत्ता मानदंडों की स्थापना (Minimum Standards of Quality)

1. NCTE ने 2014 के रेगुलेशन्स को पुनः संशोधित कर 2021 में प्रस्तावित नई रूपरेखा लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया।
2. संस्थानों को भवन, संकाय, संसाधन, पुस्तकालय, ICT लैब्स, अभ्यास शिक्षण स्कूल से संबद्धता आदि के स्पष्ट मापदंड पूरे करने होंगे।

2. ITEP (4-वर्षीय B.Ed.) के लिए विशेष मान्यता

केवल उन्हीं संस्थानों को 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) संचालित करने की अनुमति होगी जो NCTE के सभी शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे संबंधी मानकों पर खरे उतरते हों।

3. स्वीकृति और प्रत्यायन की प्रक्रिया में पारदर्शिता

1. NCTE ने **DIKSHA आधारित पोर्टल** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन, निरीक्षण और रिपोर्टिंग की प्रणाली लागू की है।
2. *Performance Grading Index (PGI)* के अनुसार संस्थानों की रेटिंग की जा रही है।

4. उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम के अंतर्गत नियामक एकीकरण

1. NEP 2020 के अनुसार, *Teacher Education* को भी *Higher Education Commission of India (HECI)* के दायरे में लाया जाएगा।
2. इससे NCTE की भूमिका नियामक के रूप में और भी अधिक *सुसंगत और मानकीकृत* होगी।

डेटा और आँकड़े (2023-24 तक)

घटक	आँकड़ा
देश में कुल मान्यता प्राप्त TEIs	16,100+
NCTE द्वारा निरीक्षणित संस्थान	12,000+
ITEP संचालित करने हेतु स्वीकृत संस्थान	87 (2023 तक)
संस्थान जिन्हें मानकों के उल्लंघन पर बंद किया गया	450+ (2018–2023)
NCTE द्वारा तैयार किए गए न्यूनतम बुनियादी ढांचे के पैरामीटर	12 प्रमुख घटक

चुनौतियाँ

समस्या	विवरण
निजी संस्थानों की अति-प्रविष्टि	अधिकतर TEIs निजी क्षेत्र में संचालित हैं, जिनमें से कई केवल औपचारिकताओं के लिए कार्य कर रहे हैं।
निरीक्षण में पारदर्शिता की कमी	निरीक्षण प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतें आईं।
विविधता के कारण मानकीकरण की कठिनाई	ग्रामीण बनाम शहरी संस्थानों में संसाधनों की असमानता।

1. समाधान एवं सुझाव

1. **प्रौद्योगिकी आधारित निरीक्षण:** पोर्टल/मोबाइल ऐप आधारित लाइव निरीक्षण प्रक्रिया।
2. **TEI Accreditation Index:** संस्थानों को 5 ग्रेड (A से E) में बाँटकर योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण अनुमति दी जाए।
3. **शिक्षक प्रशिक्षण रैंकिंग (TETI-Rank):** NIRF की तरह TEIs के लिए एक अलग रैंकिंग प्रणाली लागू की जाए।

2. अवसर (Opportunities)

1. गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण

NEP 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित **4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP)** शिक्षकों को विषयवस्तु, शिक्षाशास्त्र और व्यावहारिक ज्ञान के संतुलित समावेश के माध्यम से **गुणवत्ता-आधारित प्रशिक्षण** प्रदान करता है, जिससे उनकी *शिक्षण क्षमता, नैतिक दृष्टिकोण और व्यावसायिक दक्षता* में उल्लेखनीय सुधार होता है।

2. डिजिटल सशक्तिकरण

DIKSHA, SWAYAM, NISHTHA जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षकों को **तकनीकी दक्षता, ई-लर्निंग संसाधनों**

के उपयोग और ऑनलाइन शिक्षण विधियों में सक्षम बनाते हैं। (B. Sharma & (Gope), 2026) इससे सीखने-सिखाने की प्रक्रिया अधिक लचीली, समावेशी और नवाचारपूर्ण बनती है।

3. शोध आधारित शिक्षा

नीति शिक्षकों को शोध, एक्शन रिसर्च और मूल्यांकन आधारित शिक्षण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इससे शिक्षक न केवल ज्ञान के उपभोक्ता रहते हैं बल्कि ज्ञान सृजनकर्ता भी बनते हैं, जो शिक्षण प्रक्रिया को समस्या-आधारित और विश्लेषणात्मक बनाता है। (Richards, 1994)

4. व्यावसायिक पहचान

TET, NTA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा और योग्यता आधारित प्रमाणीकरण से शिक्षक समुदाय की सामाजिक और आर्थिक मान्यता बढ़ती है। इससे उनका व्यवसायिक आत्मविश्वास मजबूत होता है और वे समाज में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं।

3. चुनौतियाँ (Challenges)

1. पूर्व-प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए संक्रमण का संकट

NEP 2020 की नई शिक्षक शिक्षा प्रणाली में पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों का समायोजन अस्पष्ट रणनीति और पुनःप्रशिक्षण योजना के अभाव में चुनौतीपूर्ण हो गया है। इससे नीति कार्यान्वयन में विरोधाभास और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

2. डिजिटल असमानता

ग्रामीण, आदिवासी और वंचित क्षेत्रों में डिजिटल उपकरणों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी साक्षरता की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण के डिजिटलीकरण प्रयासों को बाधित करती है। इससे डिजिटल डिवाइड और अधिक गहरा हो रहा है। (Lan & Liao, 2025)

3. प्रशिक्षक क्षमता में अंतर

नई नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशिक्षकों को भी नीति और तकनीकी टूल्स की गहरी समझ होनी चाहिए, किंतु कई प्रशिक्षक नवाचार, ICT, और मूल्य आधारित शिक्षण में दक्ष नहीं हैं, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

4. संस्थागत ढांचे की कमी

अनेक राज्यों में उचित संसाधनयुक्त, प्रशिक्षित स्टाफ और अधोसंरचना वाले शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की कमी है। इससे नीति द्वारा प्रस्तावित ITEP जैसे कार्यक्रमों के विस्तार और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में बाधा आती है।

4. सुझाव (Suggestions)

1. ITEP का सार्वभौमिक कार्यान्वयन

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, ताकि देशभर में शिक्षक गुणवत्ता का एक समान मानक सुनिश्चित किया जा सके।

2. डिजिटल प्रशिक्षण हेतु विशेष योजनाएं

शिक्षक प्रशिक्षण के लिए डिजिटल संसाधनों की पहुंच और दक्षता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा विशेष योजनाएं, वित्तीय सहायता और तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जाए।

3. वेबिनार, ई-वर्कशॉप और रिसर्च फेलोशिप

शिक्षकों के लिए निरंतर अधिगम सुनिश्चित करने हेतु मासिक वेबिनार, ई-वर्कशॉप्स और विषय आधारित रिसर्च

फैलोशिप कार्यक्रम आरंभ किए जाएं, जिससे वे नवीनतम शैक्षणिक विधियों से अद्यतन रह सकें।

4. निरंतर पेशेवर विकास हेतु बाध्यता

शिक्षकों की निरंतर पेशेवर उन्नति (**Continuous Professional Development - CPD**) को नौकरी के मूल्यांकन और पदोन्नति से जोड़ते हुए बाध्यकारी बनाया जाए, ताकि गुणवत्ता में निरंतरता बनी रहे।

5. निष्कर्ष (Conclusion)

1. नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का संकेत देती है। यह न केवल शिक्षकों की पेशेवर दक्षता को उन्नत करने का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि शिक्षा प्रणाली की समग्र गुणवत्ता सुधार की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2. इस नीति के अंतर्गत प्रस्तावित एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP), डिजिटल प्लेटफॉर्म का समावेश, शिक्षक पात्रता मानकों का निर्धारण, और निरंतर व्यावसायिक विकास (CPD) जैसे पहलुओं से स्पष्ट है कि सरकार शिक्षक निर्माण को पुनःपरिभाषित करना चाहती है।
3. हालाँकि, इसकी वास्तविक सफलता इस पर निर्भर करती है कि –
4. इन नवाचारों को स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर कितनी प्रभावी रूप से लागू किया जाता है,
5. पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों को किस प्रकार से पुनःसंवर्धित किया जाता है, और
6. डिजिटल असमानताओं को किस गति और गंभीरता से समाप्त किया जाता है।
7. यदि नीति में वर्णित दिशा-निर्देशों को यथार्थ रूप में निष्पादित किया गया, तो यह निश्चय ही शिक्षा की संरचना, शिक्षकों की साख, तथा विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों में दीर्घकालिक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल होगी।

References

1. Bohra, D. S. (2024). Structure Of the B.Ed. Curriculum: Need for Reforms and Future Possibilities. *Revista Electronica De Veterinaria*, 1304–1307. <https://doi.org/10.69980/redvet.v25i2.1764>
2. Devi, S. S., & Padu, A. (2024). Historical Development Of Teacher Education In India. *Revista Electronica de Veterinaria*, 25(1S). <https://doi.org/10.69980/redvet.v25i1s.2001>
3. Garcia, G. D., & Rivera, J. P. (2025). *Strengthening Quality Assurance Systems in TEIs: A Priority for Enhancing Teacher Education*. Philippine Institute for Development Studies. <https://doi.org/10.62986/pn2025.11>
4. Kaur, J. (2025). NEP-2020 and the Shift towards Integrated Teacher Education Programmes (ITEP): Implications for Teacher Educators. *International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science*, 07(04(III)), 64–68. [https://doi.org/10.62823/ijemmasss/7.4\(iii\).8372](https://doi.org/10.62823/ijemmasss/7.4(iii).8372)
5. Lan, X., & Liao, Z. (2025). The Logical Starting Point, Realistic Dilemma and Path Selection of Digital Literacy Improvement of Rural Teachers in Primary and Secondary Schools. *Education Reform and Development*, 7(4), 63–69. <https://doi.org/10.26689/erd.v7i4.10260>
6. Richards, K. (1994). From Guessing What Teachers Think to Finding out What Teachers Know: The Need for a Research Agenda. *TESOL Quarterly*, 28(2), 401. <https://doi.org/10.2307/3587443>
7. Sharma, B., & (Gope), T. (2026). THE 4-Year Integrated Teacher Education Programme under NEP 2020: A Systematic Review of Implementation Concerns and Challenges. *International Journal of*

- Scientific Research in Modern Science and Technology*, 5(1), 12–19.
<https://doi.org/10.59828/ijrmst.v5i1.401>
8. Sharma, V., Dixit, M., & Jaiswal, V. (2025). Technology in Education: Platforms like DIKSHA and SWAYAM for Digital Learning, Bridging the Digital Divide, and Ensuring Equitable Access to Technology. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 205–209.
<https://doi.org/10.21275/sr251002115728>
9. Singh, P. K., Taywade, M., Behera, B. K., & Sahoo, B. K. (2023). Virtual Teaching in COVID-19 Era: A Medical Teacher Perspective. *Matrix Science Medica*, 7(2), 51–53.
https://doi.org/10.4103/mtsm.mtsm_1_21